रणजीत टाइम्स

इंदौर

शुक्रवार, 29 मई, 2026

वर्ष-2 | अंक-126 | कुल पृष्ठः8-Digital

RNI-NO.MPHIN/2015/64585

प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

अमेरिका और ईरान ने अस्थायी संघर्ष विराम 60 दिन बढ़ाने पर जताई सहमति

दुबई. अमेरिका और ईरान के वार्ताकारों ने गुरुवार को तीन महीने पुराने युद्ध में संघर्ष विराम को 60 दिन बढ़ाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने को लेकर एक अस्थायी समझौता किया है।

यह अधिकारी सार्वजनिक रूप से बयान देने के लिए अधिकृत नहीं था और उसने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस समझौते को अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। ईरान ने तुरंत इस संभावित समझौते की पुष्टि नहीं की।

दोनों पक्षों के बीच बना यह अस्थायी समझौता ऐसे समय में सामने आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी संघर्ष विराम कमजोर होता नजर आ रहा था।

संघर्ष विराम पर तनाव बढ़ा

अमेरिकी सेना ने गुरुवार को आरोप लगाया कि ईरान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है, जब कुवैत ने बताया कि अमेरिकी हमले के बाद उस पर मिसाइल हमला हुआ। इसे मौजूदा शांति समझौते का गंभीर उल्लंघन बताया गया। अमेरिकी सेना की मध्य कमान (सेंटकॉम) ने कहा कि बुधवार देर रात कुवैत ने ईरान से दागी गई मिसाइलों को रोक लिया। सेना ने इसे अमेरिका के प्रमुख सहयोगी देश पर हमला बताया। कुवैत ने पहले अपने क्षेत्र पर हमले की पुष्टि की थी, जबकि ईरान ने कहा कि उसने एक अमेरिकी अड्डे पर जवाबी कार्रवाई की है। हालांकि, उसने देश का नाम नहीं लिया।

जवाबी हमले और आरोप

घटना उस समय हुई, जब अमेरिकी सेना ने बुधवार देर रात ईरान पर नए हमले किए और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास चार ड्रोन मार गिराए। साथ ही ईरान के बंदर अब्बास में एक ड्रोन नियंत्रण केंद्र को भी निशाना बनाया गया। दोनों देश एक-दूसरे पर लगातार संघर्ष विराम के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पूर्ण युद्ध से बचते हुए बातचीत जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि बातचीत में प्रगति हो रही है। सोमवार को अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट और नावों पर 'आत्मरक्षा' के तहत हमले किए थे।

क्षेत्र में तनाव बढ़ा

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बंदर अब्बास हवाई अड्डे पर हुए हमले की पुष्टि की और जवाबी कार्रवाई की बात कही। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि हमला कुवैत पर था या नहीं। कुवैत ने कहा कि उसकी रक्षा प्रणाली ने मिसाइलों और ड्रोन को रोक लिया।

अमेरिका और ईरान क्या चाहते हैं?

राष्ट्रपति ट्रंप इस समझौते के जरिये होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, ईरान चाहता है कि उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं और उसकी जब्त संपत्तियां वापस की जाएं। ईरान ने यह भी मांग की है कि किसी भी समझौते में इस्राइल की लेबनान में सैन्य कार्रवाई बंद होनी चाहिए।

लेबनान और इस्राइल में भी तनाव

अप्रैल के मध्य में लेबनान-इस्राइल के बीच संघर्ष विराम हुआ था। लेकिन इसे बार-बार चुनौती मिली है। इस्राइल और लेबनान के सैन्य अधिकारी शुक्रवार को वॉशिंगटन में पहली सुरक्षा वार्ता करेंगे। इस्राइल ने हाल ही में बेरूत और दक्षिण लेबनान के टायर शहर में हवाई हमले किए, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई।

मालवा-निमाड़ के पर्यटन स्थलों की बदलेगी किस्मत

सिंहस्थ से पहले होंगे करोड़ों रुपए के विकास कार्य

इंदौर। सिंहस्थ-2028 के भव्य आयोजन को लेकर राज्य सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

हालांकि सरकार का मुख्य फोकस उज्जैन पर केंद्रित है, लेकिन आगामी सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए इंदौर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और आसपास के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का अनुमान है कि उज्जैन के साथ-साथ इन तीनों शहरों में भी श्रद्धालुओं का सर्वाधिक दबाव रहेगा।

इसी को ध्यान में रखते हुए चारों शहरों को आपस में जोड़ते हुए एक विशेष योजना बनाई जा रही है, जहां यात्री सुविधाओं से जुड़े विभिन्न विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे।

ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया मप्र छग चैप्टर के चेयरमैन हेमेंद्र सिंह जादौन ने कहा कि सिंहस्थ के समय लाखों श्रद्धालु इंदौर, उज्जैन से लेकर ओंकारेश्वर के बीच रुकेंगे। मप्र के लिए यह धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बहुत बड़ा मौका होगा। सरकार और प्रशासन इस पर लगातार बैठकें कर रहा है और कई बैठकों में हमें भी आमंत्रित किया गया है। सरकार का फोकस इस बात पर है कि सिंहस्थ के लिए मप्र आने वाले श्रद्धालु उज्जैन से लेकर इंदौर, ओंकारेश्वर और अन्य कई जगहों पर भी आरामदायक यात्रा कर सकें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही सभी योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मालवा निमाड़ के इस मॉडल पर खर्च होंगे करोड़ों रुपए

राज्य सरकार मालवा-निमाड़ क्षेत्र को धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के एक बड़े और एकीकृत मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर और महेश्वर को समाहित करने वाले इस ओंकार सर्किट के विकास पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंहस्थ के अवसर पर देश और विदेशों से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर परिवहन कनेक्टिविटी, सुलभ आवास और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। संबंधित विभाग ने इस पूरी योजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

पर्यटक केंद्रों पर मिलेंगी आधुनिक और डिजिटल सुविधाएं

ओंकार सर्किट योजना के अंतर्गत इन चारों प्रमुख धार्मिक नगरों में सर्वसुविधायुक्त यात्री सुविधा और सूचना केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आने वाले यात्रियों को आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से विभिन्न धार्मिक स्थलों का अनूठा अनुभव कराया जाएगा। पर्यटक सूचना केंद्रों में मुख्य रूप से फूड कोर्ट, किचन, डिजिटल वीआर रूम, सूचना डेस्क, प्रतीक्षालय और डोरमेट्री जैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी।

आसाराम-हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

जोधपुर। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत रद्द किए जाने के एक दिन बाद गुरुवार शाम जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया। हाईकोर्ट ने बुधवार को 2013 के चर्चित दुष्कर्म मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए उसकी अपील खारिज कर दी थी।

आसाराम के जोधपुर पहुंचने की सूचना पर एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। वह कार में बैठकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए पाल स्थित आश्रम पहुंचा। कुछ समय आश्रम में बिताने के बाद वह मेडिकल जांच के लिए एम्स गया और शाम को जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने बुधवार को अंतरिम जमानत रद्द करते हुए आसाराम की उम्रकैद की सजा को सही ठहराया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि मामले में पीड़िता की स्वतंत्रता, गरिमा और मासूमियत को गंभीर रूप से चोट पहुंची थी।

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि जिस व्यक्ति को पीड़िता भगवान मानती थी, उसी ने उसकी आस्था और भरोसे को तोड़ा। अदालत ने धार्मिक गुरुओं पर अंधविश्वास और श्रद्धा को लेकर भी कड़ी टिप्पणियां कीं। हालांकि हाईकोर्ट ने आसाराम को सामूहिक दुष्कर्म और संबंधित कुछ आरोपों से बरी कर दिया लेकिन दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा।

गौरतलब है कि आसाराम को 2018 में जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी ठहराया गया था। पीड़िता 2013 में आश्रम पहुंची थी, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया था।

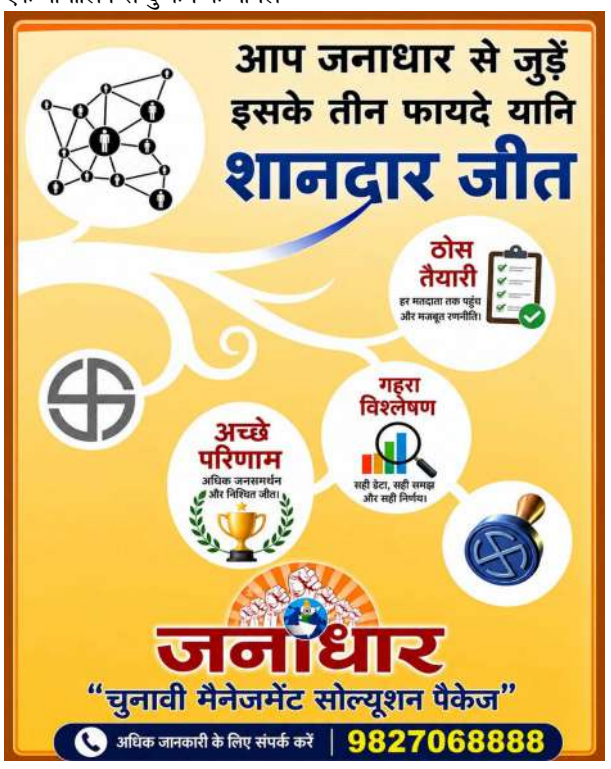

राजगढ़ में ईद पर भाईचारे की मिसाल

मुस्लिम समाज ने गौ संरक्षण को लेकर सौंपा ज्ञापन, गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करने की उठाई मांग

दिलीप पाटीदार

धार जिले के राजगढ़ में आज आपसी सद्भाव और भाईचारे की अनूठी मिसाल पेश करते हुए, आज ईद के मुबारक मौके पर राजगढ़ के मुस्लिम समाज ने गाय को 'राष्ट्र माता' घोषित करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है।

ईदगाह परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान, समाज के प्रतिनिधियों ने थाना प्रभारी समीर पाटीदार एवं तहसीलदार को यह ज्ञापन सौंपा। अपने ज्ञापन में समाज के लोगों ने कहा कि हिंदू समाज गाय को माता का दर्जा देता है और गाय के वध से उनकी भावनाएं आहत होती हैं। समाज का कहना है कि वे हिंदू समाज के साथ अपने सभी त्योहार आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाते हैं । समाज के पदाधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने एकत्रित होकर यह संदेश दिया कि देश में सभी समुदायों को मिलकर सामाजिक समरसता और पशु संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की कि गाय को "राष्ट्र माता" का दर्जा प्रदान करने पर गंभीरता से विचार किया जाए तथा गौ संरक्षण के लिए सख्त और प्रभावी योजनाएं लागू की जाएं।

ज्ञापन सौंपते समय मुस्लिम समाज के सदस्यों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय का विशेष महत्व रहा है। गाय को सेवा, त्याग और पालन-पोषण का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कहा कि गाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और कृषि क्षेत्र में उसकी उपयोगिता आज भी बनी हुई है। समाज के लोगों ने कहा कि गौ संरक्षण केवल किसी एक धर्म या समुदाय का विषय नहीं बल्कि यह पूरे देश की सांस्कृतिक विरासत और मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा विषय है।

इस अवसर पर मुस्लिम समाज के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित थे, जिनमें शौकत, सदर काजी फारूक खान, कालू खान, दिलावर खान, बालू खान, रहूब हाजी, शकील खान, गुड्डू सदर और पिरू खान सहित अहले मुस्लिम समाज के अन्य सदस्य शामिल रहे।

मुक्ति धाम की भूमि हुई अतिक्रमण मुक्त

सरपंच, उपसरपंच की पहल से ग्राम वासियों मे खुशी

बड़ोदिया (सरदारपुर)
संवाददाता दिलीप पाटीदार

बड़ोदिया और बिछीया पर किए अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ोदिया की समस्त जनता और बिछिया गाँव से पाटीदार समाज एंव पटियाला समाज के लोगों द्वारा गई बार बार प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई थी पूर्व में प्रशासन द्वारा सीमांकन कर कब्जा भी दिलाया गया था जिस पर क़ब्ज़ा धारी द्वारा वापस क़ब्ज़ा कर लिया गया था, उप सरपंच जीवन पाटीदार ने जानकारी दी की मुक्ति धाम की भूमि पर काफी लंबे समय अतिक्रमण होने के कारण बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार करने मे ग्रामीणों को परेशानीयों का करना पड़ रहा था इस समस्या को गंभीरता से लेते ग्राम पंचायत मामले को प्राथमिकता दी और संबधित अधिकारीयों से लगातार संपर्क बनाए रखा कुछ समय पहले निकली मध्यप्रदेश शासन की गाइडलाइन के अनुसार ग्राम पंचायत बड़ोदिया द्वारा तहसीलदार महोदय को अतिक्रमण हटाने के लिए

आवदेन दिया गया था पंचायत के प्रयास के बाद कल दिनांक 27/5 /2026 प्रशासनिक टीम की मौजदूगी मे अतिक्रमण हटाने की कारवाई की गई कार्रवाई के दोरान पंचायत के उप सरपंच जीवन पाटीदार, बड़ी संख्या में गाँव की समस्त जनता और बिछिया के पाटीदार एंव पटियाला समाज के लोग उपस्थिति रहे हैं अतिक्रमण हटने के बाद मुक्ति धाम परिसर को व्यवस्थित करने एवं स्वच्छ बनाने की दिशा में पंचायत और ग्रामिण जनता के जन सहयोग आगे की योजना तैयार की जा रही है जल्द ही इस पर कार्य शुरू किया जाएगा ग्रामीणों का कहना है कि मुक्ति धाम जेसी सार्वजानिक को सुरक्षित रखना हम सब की जिम्मेदारी है उप सरपंच जीवन पाटीदार ने कहा की ग्राम विकास एंव जनहित से जुड़े कार्यो को प्राथमिकता के साथ मे पूरा किया जाएगा इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी ग्राम पंचायत बड़ोदिया उपसरपंच जीवन पाटीदार तथा ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

शिवपुरी में अकीदत और भाईचारे के साथ मनाई गई ईद-उल-अजहा, अमन-चैन की मांगी गई दुआएं

शिवपुरी से ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट

शिवपुरीः त्याग और बलिदान के प्रतीक ईद-उल-अजहा (बकरीद) का पर्व शिवपुरी में हर्षोल्लास और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हुआ।

शहर की ईदगाह में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सुबह विशेष नमाज अदा की, जिसमें नमाजियों ने मुल्क में शांति, अमन-चैन और खुशहाली की विशेष दुआएं मांगी।

प्रशासन की मुस्तैदी और शांतिपूर्ण आयोजन

ईद के अवसर पर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। नमाज के दौरान ईदगाह परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए शिवपुरी कलेक्टर अर्पित शर्मा और पुलिस अधीक्षक (एसपी) यांगचेंज डोलकर

भूटिया स्वयं मौके पर उपस्थित रहे। उनके साथ एसडीओपी संजय चतुर्वेदी, देहात थाना प्रभारी विकास यादव और यातायात थाना प्रभारी रणवीर सिंह यादव सहित प्रशासनिक अमले ने कानून-व्यवस्था संभाली। शहर काजी का संदेशः एकता औ र इंसानियत का पैगाम नमाज के बाद शहर काजी बली उद्दीन अहमद सिद्दीकी ने सभी को ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यह पर्व त्याग और बलिदान की भावना सिखाता है। उन्होंने समाज से आपसी प्रेम, सामाजिक एकता और इंसानियत के पैगाम को कायम रखने की अपील की।

प्रशासन और समाज का बेहतर तालमेल

नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे के गले मिलकर बधाई दीं। इस दौरान शहर में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण देखने को मिला। ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष शरीफ खान, फरमान अली और सुहैल खान व इरशाद खान ने बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने में पुलिस प्रशासन का भरपूर सहयोग किया। प्रशासन की सतर्कता और समाज की भागीदारी के चलते शिवपुरी में ईद का त्यौहार भाईचारे के अनूठे संदेश के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ।

वीर सावरकर देशवासियों के लिए रहेंगे सदैव वंदनीय : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

मुख्यमंत्री डॉ.यादव ने महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर किया नमन

इन्दौर. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, महान स्वतंत्रता सेनानी, 'स्वार्तवीर' विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि शहीद वीर सावरकर के नाम मात्र के स्मरण से ही रोम-रोम, राष्ट्रभक्ति-साहस और आत्म गौरव के भाव से पुलकित हो उठता है। वे असह्य यातनाओं को निर्भीकता और निडरता से सह गए, लेकिन स्वतंत्रता के दीप को जलाए रखा। मां भारती की सेवा में स्वयं का होम कर देने वाले स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर देशवासियों के लिए सदा वंदनीय रहेंगे।

रणजीत टाइम्स
प्रधान संपादक : गोपाल गावंडे

आत्मिक अनुशासन को पाने का सहज, सरल मार्ग — सहजयोग

आज का युग तीव्र भागदौड़, मानसिक तनाव और अस्थिरता का दौर है। ऐसे समय में संपूर्ण विश्व आध्यात्मिक ध्यान योग की ओर अग्रसर हो रहा है। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी द्वारा विकसित सहजयोग ध्यान पद्धति को विश्वभर में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। विदेशों में हुए अनेक शोधों ने भी यह सिद्ध किया है कि सहजयोग मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है।

परम पूज्य श्री माताजी का संदेश अत्यंत सरल और गहन है — "मनुष्य को स्वयं पर दया करनी चाहिए और अपनी आत्मा को प्रकाशित करने का संकल्प लेना चाहिए।सहजयोग हमें यह अनुभव कराता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा है। जब साधक श्रद्धा और सहजता से श्री माताजी की प्रतिमा के समक्ष बैठकर पूछता है "हे माँ, क्या मैं आत्मा हूँ?", "हे माँ, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ?" तो भीतर प्रवाहित होने वाली चैतन्य लहरियाँ स्वयं उत्तर देने लगती हैं। यह अनुभव शब्दों से परे, पूर्णतः आत्मिक होता है। इस आत्मिक संवाद से पूर्व मनुष्य को आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करना होता है, जो सहजयोग में अत्यंत सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया है। आत्मसाक्षात्कार से पूर्व गुरु माँ होती हैं, किंतु आत्मसाक्षात्कार के पश्चात साधक स्वयं अपना गुरु बन जाता है। यही वह अवस्था है जहाँ मनुष्य स्वयं को पहचानना प्रारंभ करता है। अपने भीतर स्थित आत्मा का बोध और स्वयं के गुरु होने का अनुभव जीवन का सर्वोच्च ज्ञान है। सहजयोग एक मौन ध्यान साधना है, जिसमें धीरे-धीरे विचारों का प्रवाह शांत होने लगता है। अनावश्यक चिंताएँ और मानसिक अशांति सहज रूप से पंचतत्व में विलीन होने लगती हैं। साधक विचारशून्यता की अवस्था में प्रवेश करता है — जहाँ विचार रुक जाते हैं, परंतु जागरूकता पूर्णतः बनी रहती है। इसी अवस्था में मनुष्य भीतर से सुख, शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव करता है।

यह आध्यात्मिक स्थिति न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाती है, बल्कि जीवन में उत्साह, संतुलन और सकारात्मकता का संचार भी करती है। अपनी आत्मा को पहचानकर ईश्वरीय अनुकंपा का अधिकारी बनना प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत रोमांचकारी और कल्याणकारी अनुभव है। आइए, हम सभी मिलकर आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करें — जो पूर्णतः निशुल्क, सरल और सदैव उपलब्ध है।

सहजयोग पूर्णतः निशुल्क है। सहजयोग ध्यान केंद्र की जानकारी प्राप्त करने हेतु टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 पर संपर्क करें।

भोपाल मध्य प्रदेश के मयूर पार्क में 17 जून को होने वाले महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष में राजपूत मेवाड़ा समाज की बैठक संपन्न

वीर महाराणा प्रताप जयंती बनेगी ऐतिहासिक

दुर्गेश सिंह हाड़ा

आज 28 मई 2026 जून को मयूर पार्क भोपाल में मेवाड राजपूत समाज की कोर कमेटी की बैठक में बड़ा फैसलाः इस बार सिर्फ जयकारे नहीं, होंगे काम भी बड़े!

भोपाल में होगा महा-आयोजनः रक्तदान महादान शिविर प्रताप सोशल वेलफेयर फाउंडेशन के साथ - महाराणा के नाम, एक-एक बूंद देश के नाम

प्रतिभा सम्मान - समाज के होनहार बेटे-बेटियों को मंच पर सलाम

इतिहास भाषण प्रतियोगिता - युवाओं की जुबान पर होगा महाराणा का शौर्य

भव्य शौर्य शोभायात्रा - भगवा लहराएगा, भोपाल गूंजेगा महाराणा प्रताप केवल इतिहास नहीं, हमारी रगों में दौड़ता स्वाभिमान हैं।

आओ, इस जयंती पर संकल्प लें - रक्त देंगे, प्रतिभा गढ़ेंगे, इतिहास सुनाएंगे। [10:51 PM, 5/28/2026] +91 95899 91369: जिसमें सभी राजपूत सरदार उपस्थित रहे

सभी पेंशन प्रकरण अब भोपाल स्थित राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल से होंगे संचालित

जिला पेंशन कार्यालय की महत्वपूर्ण सूचना

झाबुआ. जिला पेंशन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में लागू नवीन पेंशन नियमों के अंतर्गत जिले सहित प्रदेश के सभी जिला पेंशन कार्यालयों को 01 अप्रैल 2026 से समाप्त कर भोपाल स्थित राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल में विलय कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि अब जिला पेंशन कार्यालय केवल तकनीकी समाधान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDO) को अपने समस्त पेंशन प्रकरणों का निराकरण IFMIS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन एवं ईमेल द्वारा करना होगा।

इन प्रकरणों में नियमित पेंशन, परिवार पेंशन, विकलांग पेंशन, वेतन निर्धारण तथा पुनरीक्षित पेंशन संबंधी समस्त प्रकरण शामिल हैं, जिन्हें निर्धारित प्रक्रिया अनुसार राज्य केंद्रीयकृत पेंशन प्रोसेसिंग सेल, भोपाल को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

जिला पेंशन अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि पेंशन प्रकरणों का समयबद्ध एवं सुचारू निराकरण किया जा सके।

भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों के अवकाश पर रोक

झाबुआ. जिले में वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी एवं पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार पेयजल आपूर्ति कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर्याप्त वर्षा होने तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किए गए हैं।

जारी आदेश के तहत विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं अधीनस्थ कार्यरत अमला, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं अधीनस्थ कार्यरत अमला, महाप्रबंधक, जल निगम एवं अधीनस्थ कार्यरत अमला, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, समस्त जनपद पंचायतें एवं अधीनस्थ कार्यरत अमला, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, समस्त नगर परिषद/नगर पंचायत एवं अधीनस्थ कार्यरत अमला शामिल हैं।

कलेक्टर द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अति-आवश्यक परिस्थितियों में अवकाश पर जाने से पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी अथवा अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिलों की समीक्षा बैठक आयोजित

झाबुआ. मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन की अध्यक्षता में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जनजातीय कार्य, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, सुशासन, कानून-व्यवस्था, गेहूं उपार्जन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य सचिव द्वारा खरीफ सीजन हेतु प्रदेश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी देते हुए किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। एग्रिस्टैक पर शत-प्रतिशत खातों की मैपिंग, उर्वरक उठाव के बाद किसानों का सत्यापन तथा किसान रथ के प्रभावी अनुश्रवण पर विशेष जोर दिया गया। असामयिक वर्षा की स्थिति को देखते हुए गेहूं के सुरक्षित भंडारण हेतु तिरपाल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा गेहूं खरीदी, परिवहन, भंडारण एवं किसानों के भुगतान की प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आईएमडी के अलर्ट पर सतत निगरानी रखते हुए पेयजल एवं संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित एवं निर्बाध पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए जल वितरण नेटवर्क का सर्वे, रिसाव की त्वरित मरम्मत, जल गुणवत्ता परीक्षण तथा दूषित जल आपूर्ति रोकने के निर्देश दिए। सीएम हेल्पलाइन में पेयजल एवं सीवेज संबंधी शिकायतों के निराकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया। बैठक में एकल नलजल योजनाओं को समयसीमा में पूर्ण करने, ग्राम पंचायतों को हस्तांतरण, जल योजनाओं के सतत संचालन तथा जल उपभोक्ता प्रभार के नियमित संग्रहण पर भी निर्देश दिए गए। खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विशेष जांच दल गठित कर सतत कार्रवाई करने तथा स्कूल, कॉलेज एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में "ईट राइट" अभियान को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण, पीएम किसान, राशन कार्ड, फसल ऋण, बीमा एवं अन्य प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। कृषि विभाग को नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्ती से नियंत्रण, कृषि यंत्रों की मॉनिटरिंग तथा स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। बैठक में शैक्षणिक संस्थानों के 500 मीटर क्षेत्र को "ड्रग फ्री जोन" घोषित कर प्रभावी कार्रवाई करने, जागरूकता शिविर आयोजित करने तथा राष्ट्रीय मादक पदार्थ हेल्पलाइन-1933 के प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। मिशन कर्मयोगी अंतर्गत सभी लोकसेवकों को आई-गोट पोर्टल पर सक्रिय करने तथा प्रत्येक कर्मचारी द्वारा कम से कम एक एआई कोर्स पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही "साधना सप्ताह" के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सम्मानित करने पर जोर दिया गया।प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लंबित आवेदनों के सत्यापन, जियो-टैगिंग एवं परियोजनाओं की स्वीकृति शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सड़क सुरक्षा के तहत बसों में फायर सेफ्टी उपकरणों की जांच, अवैध मॉडिफिकेशन पर रोक, ब्लैक स्पॉट सुधार तथा राह-वीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी निर्देश दिए गए।

बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को कृत्रिम गर्भाधान एवं नस्ल सुधार कार्यक्रमों में प्रगति लाने, जबकि मत्स्य विभाग को एकीकृत मत्स्योद्योग नीति 2026 अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के शीघ्र अनुमोदन के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने विस्फोटक अधिनियम के अनुपालन की समीक्षा करते हुए विस्फोटक निर्माण, भंडारण एवं परिवहन इकाइयों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट, पुलिस अधीक्षक श्री देवेन्द्र पाटीदार, वनमण्डलाधिकारी श्री भारत सोलंकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्र सिंह चौहान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एमबीबीएस की फर्जी डिग्री और सरकारी भर्ती का मास्टरमाइंड हीरा सिंह कौशल निलंबित, आदेश जारी

भोपाल। फर्जी एमबीबीएस डिग्री और सरकारी भर्ती रैकेट का मास्टरमाइंड हीरा सिंह कौशल पर आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई कर दी है। हीरा सिंह को स्वास्थ्य विभाग ने निलंबित कर दिया है।

हीरा सिंह सीहोर जिले के बिलकिसगंज में रेडियोग्राफर के पद पर पदस्थ था। अमर उजाला ने 21 मई को 'MP: फर्जी डिग्री रैकेट के मास्टरमाइंड हीरा सिंह का आका कौन? 2021 में जेल गया फिर भी सरकारी नौकरी में लौट आया' इस शीर्षक से खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इस मामले को सीहोर सीएमएचओ डॉ.सुधीर डेहरिया और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे थे। इस संबंध में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला तक जानकारी पहुंची तो उन्होंने तुरंत गिरफ्तार हीरा सिंह को निलंबित करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कार्रवाई हुई। बता दें दमोह और जबलपुर में तीन फर्जी एमबीबीएस की डिग्री से डॉक्टर पकड़ में आए थे। उन्होंने हीरा सिंह का नाम लिया था। इसके बाद दमोह पुलिस ने 20 मई को हीरा सिंह को भोपाल से गिरफ्तार किया। अब तक 12 फर्जी डिग्री से डॉक्टर के नाम सामने आए हैं। पुलिस मामले में जांच करर ही है।

फर्जी डिग्री और भर्ती घोटाले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और विभागीय संरक्षण पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि हीरा सिंह लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम की संविदा भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लोगों के संपर्क में रहकर फर्जी डिग्री, जाली मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन और नौकरी दिलाने का नेटवर्क संचालित कर रहा था।सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 2021 में बैतूल में फर्जी नियुक्ति पत्र मामले में गिरफ्तार होकर जेल जाने के बावजूद वह दोबारा सरकारी नौकरी में कैसे लौट आया। उस मामले में आरोप था कि उसने युवाओं से लाखों रुपये लेकर सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और कई लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी जारी किए गए थे। शिकायत के बाद वह करीब छह महीने जेल में रहा, लेकिन जमानत पर बाहर आने के बाद फिर से विभाग में सक्रिय हो गया।

जानकारी के अनुसार हीरा सिंह वर्ष 2007 में मुलताई में एक्स-रे टेक्निशियन के पद पर नियुक्त हुआ था। इसके बाद उसने विभागीय संपर्कों और सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर कथित रूप से फर्जी नियुक्तियों और डिग्री नेटवर्क को फैलाया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि उसने कितने लोगों को नौकरी दिलाई और इस पूरे नेटवर्क में किन अधिकारियों या कर्मचारियों की भूमिका रही। मामले में यह आरोप भी सामने आए हैं कि हीरा सिंह बिना नियमित ड्यूटी किए वेतन प्राप्त कर रहा था। वहीं, सीहोर सीएमएचओ डॉ. सुधीर डेहरिया ने बताया था कि आरोपी एक मई से अवकाश पर था और उसके खिलाफ लगे आरोपों की विभागीय जांच कराई जाएगी। मोह

और जबलपुर में फर्जी डॉक्टरों के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने भोपाल से हीरा सिंह को गिरफ्तार किया था। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा निलंबन की कार्रवाई के बाद पूरे मामले में विभागीय जवाबदेही और संभावित मिलीभगत की जांच तेज होने की संभावना है।

पॉश इलाके में विस्थापितों को फ्लैट देने का विरोध, रहवासी ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

इंदौर. विकास प्राधिकरण द्वारा गुलमोहर कॉम्प्लेक्स में विस्थापित परिवारों को पुनर्वासित करने के फैसले के विरोध में वहां के स्थानीय नागरिकों ने लामबंद होना शुरू कर दिया है।

रहवासी संघ के अध्यक्ष रौनक राय के नेतृत्व में स्थानीय निवासियों ने इस शासकीय निर्णय के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है। आज सभी रहवासियों ने कॉम्प्लेक्स के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला रहवासियों से बात करने पहुंचे और उनकी मांगों पर आईडीए में बात करने का आश्वासन दिया। विधायक ने कहा कि जल्द ही बीच का रास्ता निकाला जाएगा और रहवासियों को आने वाली परेशानियों से बचाया जाएगा।

रहवासियों ने सुझाए विकल्प

स्थानीय रहवासी संघ द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी के अनुसार, गुलमोहर कॉम्प्लेक्स मूल रूप से एलआईजी श्रेणी की आवासीय योजना है, जिसमें कुल 334 फ्लैट्स निर्मित हैं। वर्तमान में इनमें से केवल 90 फ्लैट्स ही रिक्त हैं, जिनका क्षेत्रफल 667 वर्ग फीट है। इसके विपरीत, जिन विस्थापित परिवारों को यहां लाकर बसाने की योजना बनाई जा रही है, उनकी कुल संख्या 200 से भी अधिक है। रहवासियों का तर्क है कि इतने कम फ्लैट्स में इतने अधिक परिवारों को समाहित करना व्यावहारिक रूप से पूरी तरह असंभव है और इस जबरन व्यवस्था के कारण भविष्य में गंभीर कानूनी पेच और विवाद उत्पन्न होना तय है। इस समस्या के समाधान के रूप में रहवासियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को एक बेहतर विकल्प भी सुझाया है। नागरिकों के मुताबिक, इस कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल नजदीक ही नवनिर्मित अमलतास कॉम्प्लेक्स स्थित है, जहां 550 वर्ग फीट के लगभग 450 फ्लैट पूरी तरह से खाली पड़े हैं। यह एक बहुमंजिला और पूर्णतः आधुनिक इमारत है जो नई होने के साथ-साथ खाली भी है, इसलिए विस्थापितों के पुनर्वास के दृष्टिकोण से यह हर तरह से उपयुक्त है। रहवासियों की इस दलील और सुझाव पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिलाया है।

जर्जर बुनियादी सुविधाएं और रखरखाव पर उठते गंभीर सवाल

आंदोलन कर रहे नागरिकों ने इंदौर विकास प्राधिकरण की कार्यप्रणाली और निर्माण गुणवत्ता पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। निवासियों का कहना है कि गुलमोहर कॉम्प्लेक्स में पहले से ही रहने वाले लोग पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं और इमारतों में लगी लिफ्ट भी आए दिन तकनीकी खराबी के कारण बंद रहती हैं। नागरिकों ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण कई साल से न बिकने वाले इन फ्लैट्स को विस्थापितों को सौंपकर अपनी नाकामियों और जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहता है। इसके अतिरिक्त, एक बड़ी व्यावहारिक समस्या यह भी है कि परिसर में पानी की सुचारू आपूर्ति बढ़ाने के लिए भी कोई लिखित गारंटी देने के लिए प्राधिकरण फिलहाल तैयार नहीं दिख रहा है।

विस्थापित होने वाले परिवारों को मिलते हैं ईडब्ल्यूएस के मकान

प्रशासनिक मामलों के जानकारों का इस विषय में स्पष्ट मानना है कि अब तक की व्यवस्था के अनुसार शासकीय योजनाओं में विस्थापित होने वाले परिवारों को केवल ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी के छोटे मकान ही आवंटित किए जाते रहे हैं। यदि इस मामले में नियमों को शिथिल कर गुलमोहर कॉम्प्लेक्स जैसे बड़े एलआईजी फ्लैटों में इन्हें बसाया जाता है, तो यह प्रशासनिक इतिहास में एक ऐसी गलत और नई परिपाटी की शुरुआत होगी, जिससे भविष्य में मध्य प्रदेश के अन्य शहरों के विस्थापित भी सरकार से बड़े फ्लैटों की मांग करने लगेंगे।

सोमवार से चल रहा प्रदर्शन

इससे पहले सोमवार और मंगलवार को बड़ी संख्या में रहवासी एकत्र होकर इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय भी गए थे। वहां आयोजित जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी परिक्षित झाडे और संभागायुक्त सुदामा खाडे को एक लिखित ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं थी। प्रदर्शनकारी नागरिकों ने प्रशासन को दो टूक चेतावनी दी थी कि यदि प्राधिकरण ने अपनी इस मनमानी नीति को तुरंत नहीं रोका, तो आने वाले दिनों में स्थानीय स्तर पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा, जिसमें भूख हड़ताल और पुतला दहन जैसे उग्र कदम शामिल होंगे।

जल संरक्षण अभियान को जनभागीदारी से मिला नया आयाम

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्राचीन अहिल्या कुंड के जीर्णोद्धार कार्य का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर उन्होंने विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर जल संरक्षण के प्रति जनजागरण का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री गोलू शुक्ला, श्री गौरव रणदिवे, श्री श्रवण सिंह चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। साथ ही पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह, आईजी श्री अनुराग, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन, डीआईजी श्री मनोज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री राजेंद्र वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जल गंगा संवर्धन अभियान की जानकारी दी और सभी से जल संरक्षण को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जल बचा कर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अपने संबोधन में संत कबीरदास एवं संत रहीम के दोहों का उल्लेख करते हुए जल की महत्ता को सरल एवं प्रेरणादायी ढंग से समझाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल को जीवन, संवेदना और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। उन्होंने ग्रामीणों से वर्षा जल संरक्षण, तालाबों और कुंडों के संरक्षण तथा जल के विवेकपूर्ण उपयोग का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और जल गंगा संवर्धन अभियान के माध्यम से पारंपरिक जल स्त्रोतों के पुनर्जीवन का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि जनसहभागिता से ही जल संरक्षण के प्रयास सफल होंगे और आने वाले समय में प्रदेश जल समृद्धि की दिशा में नई पहचान बनाएगा।

फिक्स डिपॉजिट और बचत योजनाओं के नाम पर करोड़ों की ठगी

वीएसीएल सोसायटी के पदाधिकारियों पर FIR

भोपाल। फिक्स डिपॉजिट और बचत योजनाओं में ज्यादा ब्याज और कम समय में रकम दोगुनी-तिगुनी करने का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले वीएसीएल जन सहयोग क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के पदाधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने मामला दर्ज किया है।

जांच में सामने आया है कि संस्था ने करीब 3000 लोगों से निवेश के नाम पर बड़ी रकम जमा कराई और बाद में पैसा वापस नहीं किया। यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण युवा मंच के संयोजक अशोक कुमार टाटा की शिकायत पर की गई। ईओडब्ल्यू जांच में प्रथम दृष्टया यह साबित हुआ कि संस्था के पदाधिकारियों ने लोगों को अधिक ब्याज, कम समय में रकम दोगुनी-तिगुनी होने और रोजगार दिलाने का झांसा देकर निवेश कराया। ईओडब्ल्यू थाना भोपाल में संस्था के तत्कालीन अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष बीएस चौहान, अभिषेक शर्मा सहित कई संचालकों और सहयोगियों

के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409, 120-बी तथा मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 की धारा 6(1) के तहत FIR दर्ज की गई है। जांच में पता चला कि सोसायटी का पंजीयन 3 सितंबर 2013 को हुआ था और इसका कार्यालय भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित 11 नंबर स्टॉप पर संचालित होता था। संस्था ने डेली डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और मासिक आय योजना जैसी कई योजनाएं शुरू की थीं। निवेशकों को "जन सहयोग कैश क्रेडिट सर्टिफिकेट" जारी कर 12 प्रतिशत या उससे अधिक ब्याज देने का वादा किया जाता था।

बैंक रिकॉर्ड की जांच में सामने आया कि संस्था के खाते में करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपये जमा हुए। जांच एजेंसी के अनुसार खाते का संचालन मुख्य रूप से राकेश शर्मा कर रहे थे। कई निवेशकों ने दस्तावेज और प्रमाणपत्र देकर बताया कि समय पूरा होने के बाद भी उनकी जमा राशि वापस नहीं की गई। जांच में यह भी सामने आया कि जब लोगों ने पैसा वापस मांगना शुरू किया तो संस्था का कार्यालय बंद रहने लगा और पदाधिकारियों ने मोबाइल फोन बंद कर लिए। कुछ निवेशकों के चेक भी बाउंस हुए। संस्था से जुड़े कर्मचारियों ने भी बयान दिया कि उन्हें वेतन तक नहीं मिला। ईओडब्ल्यू को जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं, जिनसे पता चला कि संस्था के संचालन के दौरान आरोपी राकेश शर्मा ने करोड़ों रुपये की जमीन खरीदी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अधिक तापमान में रखें सभी नागरिक स्वास्थ्य का ध्यान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बचाव के आवश्यक उपाय अपनाने का किया आहवान

बुरहानपुर.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्रीष्मकाल के दौरान प्रदेश में बढ़े हुए तापमान और अधिक गर्मी से होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने और बचाव के आवश्यक उपाय अपनाने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी देश के विभिन्न भागों में तापमान के लगातार बढ़ने और दैनिक जीवन में गर्मी से होने वाली कई कठिनाइयों के बढ़ने पर चिंता व्यक्त करते हुए देशवासियों से अधिक से अधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों से स्वयं और विशेष रूप से बच्चों को हाइड्रेटेड बने रहने और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ वॉटर बॉटल रखने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्यासे व्यक्तियों को पानी उपलब्ध करवाने के लिए अपने घरों और दुकानों के बाहर मटके में पेयजल की व्यवस्था रखने वाले सेवाभावी नागरिकों की सराहना की है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड आदि स्थानों पर यात्रियों को पानी पिलाने वाले सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों को इस नेक कार्य के लिए प्रोत्साहित करने की जरूरत बताई है।

खुशियों की दास्तां-दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना- मात्र 5 रुपये में मिल रहा भरपेट भोजन

बुरहानपुर. प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को आवश्यक सुविधाएं सहज, सुलभ एवं सम्मानपूर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना है, जो गरीब, श्रमिक, जरूरतमंद एवं कम आय वर्ग के नागरिकों के लिए कारगर है। योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भूखा न रहे और उसे कम लागत में पौष्टिक भोजन उपलब्ध हो सके।

बुरहानपुर में संचालित हो रहे दीनदयाल रसोई केन्द्र

बुरहानपुर जिले में भी आमजनों की सुविधा के लिए दीनदयाल अंत्योदय रसोई केन्द्र संचालित हैं। ऐसा ही एक रसोई केन्द्र नगर निगम बुरहानपुर अंतर्गत आर्या नवयुग शिक्षा समिति भोपाल द्वारा लालबाग सागर टॉवर के पास संचालित किया जा रहा है। यहां आने वाले नागरिकों को मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

सम्मानपूर्वक भोजन के लिए बेहतर व्यवस्थाएं

रसोई केन्द्र में नागरिकों के बैठकर भोजन करने के लिए टेबल एवं बैंच की व्यवस्था की गई है, ताकि जरूरतमंद नागरिक सम्मानपूर्वक भोजन ग्रहण कर सकें। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रमिक, राहगीर एवं जरूरतमंद नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

अलग-अलग दिवसों में तय है भोजन मेन्यू

रसोई केन्द्र में अलग-अलग दिवसों में तय मेन्यू अनुसार पौष्टिक एवं संतुलित भोजन परोसा जाता है। वहीं रविवार को अवकाश रहता है।

महिलाओं को भी मिल रहा रोजगार

रसोई केन्द्र में भोजन तैयार करने का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिससे उन्हें भी रोजगार एवं आत्मनिर्भरता का अवसर मिल रहा है। केन्द्र के माध्यम से प्रतिदिन करीबन 100 से 120 जरूरतमंदों को भोजन प्राप्त होता है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना केवल भोजन उपलब्ध कराने की योजना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग को सम्मानपूर्वक सहयोग देने की पहल है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में संचालित यह योजना प्रदेश में जनसेवा एवं सामाजिक संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बन रही है।

"श्रम प्रहरी" बन अपंजीकृत संस्थानों की जानकारी देकर श्रमिक कल्याण में करें योगदानटोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दे सूचना

बुरहानपुर. श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशाएं और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। आम नागरिक "श्रम प्रहरी" के रूप में आगे आकर अपंजीकृत संस्थानों और निर्माण स्थलों की गोपनीय सूचना दे सकते हैं, जिससे श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक सुचारू रूप से पहुँचाया जा सके।

श्रमिकों के हितों के संरक्षण और कार्यस्थल पर उनके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थानों एवं निर्माण स्थलों का श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीयन होना अनिवार्य है, पंजीकरण न होने की स्थिति में श्रमिक सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

श्रम विभाग द्वारा कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए वर्तमान में संचालित व पंजीकृत निर्माण कार्यों, अति-खतरनाक और अन्य कारखानों की ऑनलाइन सूची विभाग के आधिकारिक पोर्टल संइवनतण्उचण्हवअण्पद पर सार्वजनिक कर दी गई है। आम नागरिक इस पोर्टल पर जाकर पंजीकृत संस्थानों की जांच कर सकते हैं और यदि कोई भी संस्थान या निर्माण स्थल अपंजीकृत पाया जाता है, तो वे "श्रम प्रहरी" की भूमिका निभाते हुए इसकी सूचना टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर दे सकते हैं। नागरिकों द्वारा प्राप्त प्रामाणिक सूचनाओं के आधार पर श्रम विभाग द्वारा संबंधित स्थलों का त्वरित परीक्षण कर आवश्यक कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पंजीकरण न कराने वाले नियोजकों को 2 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान

कारखाना अधिनियम-1948 यह प्रावधानित करता है कि ऐसा कोई भी परिसर, जहां 20 या अधिक श्रमिक विद्युत शक्ति के साथ अथवा बिना विद्युत शक्ति के विनिर्माण कार्य में नियोजित हैं, उस संस्थान को मुख्य कारखाना निरीक्षक से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके साथ ही, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम-1996 के तहत नियोजक का यह दायित्व है कि वह किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इसकी सूचना अनिवार्य रूप से श्रम विभाग को उपलब्ध कराए। संस्थानों का पंजीकरण न कराने वाले नियोजकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का भी कड़ा प्रावधान है, जिसके तहत कारखानों के मामले में अधिकतम 1 लाख रुपये का जुर्माना अथवा 2 वर्ष तक का कारावास या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। इसी प्रकार, निर्माण स्थलों का पंजीकरण नहीं कराए जाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना अथवा 3 माह तक का कारावास या दोनों की कार्रवाई की जा सकती है। विभाग ने सभी नियोजकों को सचेत किया है कि वे किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपनी संस्था एवं निर्माण कार्य का पंजीकरण तत्काल सुनिश्चित करें।

जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक अब 29 मई को

नीमच. कलेक्टर श्री हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की कार्यकारी समिति की बैठक 29 मई 2026 को सायं 4 बजे कलेक्टोरेट सभागृह नीमच में आयोजित की जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ.दिनेश प्रसाद ने समिति के सभी सदस्यों से बैठक में उपस्थित होने का आगृह किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने प्रदर्शन के नए आयाम स्थापित किए

उज्जैन। खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार 1.87 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का आंकड़ा पार किया है।

वित्त वर्ष 2025-26 में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 1,87,105 करोड़ रुपये के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है।

केवीआईसी अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने नई दिल्ली के गांधी दर्शन, राजघाट स्थित कार्यालय में वित्त वर्ष 2025-26 के अनंतिम आंकड़े जारी करते हुए क्षेत्र की रिकॉर्ड प्रगति को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केवीआईसी की योजनाएं 'वोकल फॉर लोकल' और 'लोकल टू ग्लोबल' के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति दे रही हैं।

पिछले 12 वर्षों में उत्पादन में 380 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें 2013-14 में 26,109 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1,25,296 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार बिक्री में 501 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें 2013-14 में 31,154 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 1,87,105 करोड़ रुपये हो गया है। रोजगार सृजन में भी 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिससे अब 2.04 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है।

खादी वस्त्रों के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2013-14 में 811 करोड़ रुपये का उत्पादन बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 390 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,974 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं बिक्री 1,081 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 628 प्रतिशत वृद्धि के साथ 7,869 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

ग्रामोद्योग क्षेत्र का नया रिकॉर्ड बनाते हुए वर्ष 2013-14 में जहां उत्पादन 25,298 करोड़ रुपये था वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में लगभग 380 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 1,21,322 करोड़ रुपये हो गया है। इसी प्रकार बिक्री 30,073 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 496 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,79,236 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की उपलब्धियों में वित्त वर्ष 2025-26 में 66,494 नई इकाइयों की स्थापना की गई जिनके माध्यम से 7,31,434 लोगों को रोजगार मिला। योजना की शुरुआत से अब तक कुल 10,84,679 इकाइयों के माध्यम से लगभग 97.95 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कारीगरों का सशक्तिकरण करते हुए अभी तक 3,23,006 मशीनें, टूलकिट एवं उपकरण वितरित किए जा चुके हैं जिनमें वित्त वर्ष 2025-26 में 37,769 शामिल हैं।

महिला सशक्तिकरण में केवीआईसी की अग्रणी भूमिका रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 59 प्रतिशत महिला प्रशिक्षु यानी 47,382 महिलाएं शामिल हुईं। PMEGP के तहत 28,180 महिला उद्यमियों द्वारा इकाइयों की स्थापना की गई जिससे 3,09,980 महिलाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। खादी क्षेत्र में लगभग 5 लाख कारीगरों में 80 प्रतिशत से अधिक महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र को महिला नेतृत्व आधारित आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनाती है।

कारीगरों के पारिश्रमिक में 275 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 2013-14 में 4 रुपये प्रति हैंक से बढ़कर वर्तमान में 15 रुपये प्रति हैंक हो गया है।

इसके साथ ही सरकारी आपूर्ति, प्रदर्शनी बिक्री और राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है।

अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रभावी मार्गदर्शन, महात्मा गांधी की प्रेरणा तथा देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत करोड़ों कारीगरों की मेहनत को दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर सिंहस्थ के लिए विकास कार्यों की मिल रही सौगात

फ्रीगंज ओवर ब्रिज समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर आगे का कार्य शुरू करें- संभाग आयुक्त श्री सिंह

उज्जैन/ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर सिंहस्थ 2028 के विश्व स्तरीय भव्य आयोजन के लिए शहर में विकास कार्यों की सौगातें मिली है।

निर्माणाधीन कार्यों के पूर्ण होने के बाद सिंहस्थ के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय आमजनों को भी सुविधा मिलेगी।

निर्माण कार्यों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर प्रशासन द्वारा गुणवत्ता पूर्ण और तेज गति से निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने पर जोर दिया जा रहा है।

सिंहस्थ के निर्माण कार्यों के नियमित निरीक्षण के तहत गुरूवार को संभागायुक्त सह सिंहस्थ मेला अधिकारी श्री आशीष सिंह और कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने शहर के प्रमुख मार्गों को जोडऩे के लिए निर्माणाधीन महत्वपूर्ण ब्रिज निर्माण कार्यों का जायजा लिया।

आवागमन की सुविधा के लिए नए ब्रिज निर्माण कार्यों में चामुंडा माता चौराहा से फ्रीगंज की ओर निर्माणाधीन रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जानकारी दी गई कि ब्रिज निर्माण कार्य प्रगतिरत होकर अब ग्रांड होटल के सामने से निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

संभागायुक्त श्री सिंह ने निर्देश दिए कि आगे के निर्माण कार्य के लिए मार्ग में बैरिकेडिंग कर चद्दर लगाकर कार्य प्रारंभ किया जाए। जिससे इस मार्ग में आवागमन के दौरान कोई समस्या नही हो। संभागायुक्त ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान उज्जैन-मक्सी मार्ग पर शहर के पुराने समपार क्र.2 पूर्व ब्रिज के समानांतर उज्जैन-इंदौर रेल सेक्शन पर आईटीआई के सामने निर्माणाधीन टू लेन आरओबी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मौके पर ब्रिज निर्माण का कार्य प्रगतिरत पाया गया। यहां पर संभागायुक्त ने ब्रिज निर्माण की तकनीकी जानकारी लेकर निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के लिए लैब में नियमित टेस्टिंग कराने के निर्देश दिए। इसके बाद संभागायुक्त श्री सिंह और कलेक्टर श्री सिंह ने उज्जैन-लालपुर-मक्सी मार्ग (पंचक्रोशी मार्ग) समपार क्र.7 पर पूर्व से निर्माणाधीन आरओबी के समानांतर अतिरिक्त आरओबी निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभागायुक्त श्री सिंह ने ब्रिज निर्माण में पाइल की जानकारी लेकर अतिरिक्त मशीनरी लगाकर कार्य तेज गति से करने के निर्देश दिए।

संभागायुक्त श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मंशानुरूप विकास सभी विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर मौजूद रहकर कार्य गुणवत्ता का परीक्षण भी करें।

ग्लोबल स्टैंडर्ड पर तैयार हो रहे विक्रमादित्य के इंजीनियर्स

कुलगुरु प्रो. भारद्वाज की अनूठी पहल से छात्र सीख रहे इंडस्ट्री की बारीकियां

उज्जैन। राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और व्यावहारिक दक्षता को नया आयाम देते हुए सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के 'स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' के छात्रों ने देवास स्थित प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाई 'फ्लूइडोमेट लिमिटेड' का शैक्षणिक भ्रमण किया।

विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज के मार्गदर्शन में आयोजित इस उच्चस्तरीय दौरे का मुख्य उद्देश्य छात्रों को कक्षा में सीखी गई जटिल इंजीनियरिंग अवधारणाओं को वास्तविक और आधुनिक औद्योगिक परिवेश में क्रियान्वित होते हुए दिखाना था, ताकि वे भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए पूरी तरह सक्षम बन सकें।इस ज्ञानवर्धक भ्रमण के दौरान छात्रों ने फ्लूइडोमेट लिमिटेड की अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयों ,गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रियाओं और रोबोटिक व मशीनीकृत संचालन को बारीकी से समझा। वहां मौजूद देश के अनुभवी और वरिष्ठ इंजीनियरों ने छात्रों को हाइड्रोलिक कपलिंग और ट्रांसमिशन तकनीक की बारीकियों व उनके लाइव ऑपरेशन्स से रूबरू कराया, जो छात्रों के लिए एक व्यावहारिक अनुभव रहा।

विश्वविद्यालय के छात्रों को वैश्विक कार्य-दक्षता और कौशल से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण दौरे पर मार्गदर्शन देते हुए कुलगुरु प्रो. अर्पण भारद्वाज ने कहा कि "आज के दौर में सैद्धांतिक ज्ञान अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक व्यावहारिक अनुभव और इंडस्ट्री का एक्सपोजर ही छात्रों को एक सफल व वैश्विक स्तर का इंजीनियर बनाता है। हमारा मुख्य ध्येय विश्वविद्यालय के छात्रों को केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि उन्हें आज की वैश्विक दक्षता और मांग से जोड़ना है। फ्लूइडोमेट लिमिटेड जैसे उच्च तकनीकी उद्योगों का यह दौरा हमारे छात्रों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर साबित होगा, जिससे वे कॉर्पोरेट और कोर-इंजीनियरिंग सेक्टर की बदलती जरूरतों को समझकर खुद को देश-विदेश के अग्रणी उद्योगों के अनुकूल तैयार कर सकेंगे।"

संस्थान के इस अभिनव प्रयास पर हर्ष व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि ऐसे औद्योगिक भ्रमणों से विद्यार्थियों को इंडस्ट्री की वास्तविक कार्यशैली और वहां के कड़े अनुशासन का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है, जिससे उनका विजन बड़ा होता है। हम भविष्य में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के साथ ऐसे संवाद और दौरों का सिलसिला जारी रखेंगे। वहीं 'स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी' के निदेशक डॉ. संदीप तिवारी ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन का निरंतर यह प्रयास है कि हमारे छात्र किताबी दायरे से बाहर निकलकर सोचें। इस आयोजन के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने फ्लूइडोमेट लिमिटेड के प्रबंधन के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया, जिन्होंने भावी राष्ट्र निर्माताओं को अपने परिसर में सीखने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक भ्रमण को इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक श्री शिवम शर्मा, श्री खेमराज बैरागी, श्रीमती अंजलि उपाध्याय एवं श्री रघुनंदन बघेल के मार्गदर्शन व नेतृत्व में संपन्न कराया गया।

अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

अवैध रूप से संग्रहित बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर जप्त

इन्दौर. इंदौर में अग्नि सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन लगातार सतर्कता और सख्ती के साथ कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज शहर के मध्य स्थित महाराजा कॉम्प्लेक्स में बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान एक अवैध रूप से कब्जाई गई दुकान में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए गैस से भरे हुए 25 गैस सिलेंडर जब्त किए। बताया गया कि सिलेंडरों का संग्रहण सुरक्षा मानकों के विपरीत किया जा रहा था, जिससे आगजनी जैसी गंभीर दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। मामले की विस्तृत जांच की जा रही है।

सांची की वैश्विक पहचान इन पावन अस्थि अवशेषों से है-मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल

भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के पवित्र अस्थि अवशेष मंगोलिया विहार के लिए ससम्मान रवाना

भोपाल. राजाभोज विमानतल परिसर में गुरुवार को भगवान बुद्ध के परम शिष्यों श्री सारिपुत्र एवं श्री महामौद्गल्यायन के पवित्र अस्थि अवशेषों को 'मंगोलिया विहार' (मंगोलिया यात्रा) हेतु पूर्ण धार्मिक विधि-विधान, मंत्रोच्चार और गरिमामयी वातावरण के बीच ससम्मान विदाई दी गई।

इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि आज का दिन भारत और मध्य प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के समान है। भगवान बुद्ध के महान शिष्यों के ये पवित्र अस्थि अवशेष केवल हमारी आध्यात्मिक धरोहर ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति, करुणा और सौहार्द के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इन पवित्र अवशेषों का संरक्षण संपूर्ण विश्व में केवल भारत, श्रीलंका और म्यांमार में ही है, जो हमारे देश और प्रदेश के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सांस्कृतिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार भारत की आध्यात्मिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

श्री पटेल ने अपने पूर्व संस्कृति मंत्री कार्यकाल का उल्लेख करते हुए बताया कि सांची आने वाले विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए स्थानीय भाषाओं में साइन बोर्ड स्थापित करने की नीति बनाई गई थी। इसी के अंतर्गत श्रीलंका से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सांची में उनकी भाषा में भी संकेतक लगाए गए, जिससे उन्हें आत्मीयता का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि सांची केवल अपने भव्य स्तूपों के कारण विश्व धरोहर स्थल नहीं है, बल्कि इन चैतन्य अस्थि अवशेषों की पावन उपस्थिति के कारण विश्वभर की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। पूर्व में इन अवशेषों की थाईलैंड यात्रा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मंगोलिया के साथ भारत के सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक संबंध अत्यंत प्राचीन हैं और यह यात्रा उन संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

विकास के साथ विरासत का संरक्षण हमारा संकल्प — कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा

कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने कहा कि भगवान बुद्ध की यह विरासत विश्व बंधुत्व की अमूल्य धरोहर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मूल मंत्र "विकास भी, विरासत भी" का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन इस संकल्प को पूरी निष्ठा के साथ धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे अंतरराष्ट्रीय एवं आध्यात्मिक आयोजन विश्व समुदाय को यह संदेश देते हैं कि भारत प्राचीन काल से विश्वगुरु रहा है और अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के कारण सदैव विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ है, जो भगवान बुद्ध से जुड़े अनेक पवित्र स्थलों के निकट स्थित है। ऐसे में भोपाल में इस ऐतिहासिक एवं आध्यात्मिक अवसर का साक्षी बनना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस आयोजन के माध्यम से मध्यप्रदेश की पहचान मंगोलिया सहित मध्य एशिया के देशों तक और अधिक सुदृढ़ होगी।

सांची आध्यात्मिक वैभव का अनुपम खजाना — पूज्य बानगल उपतिस्स नायक थेरी

समारोह में विशेष रूप से उपस्थित बौद्ध धर्मगुरु पूज्य बानगल उपतिस्स नायक थेरी ने कहा कि सांची केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक वैभव का अनुपम खजाना है। उन्होंने कहा कि बौद्ध जगत में इस पवित्र स्थल की महिमा अतुलनीय है। उन्होंने बताया कि पूर्व में जब ये पवित्र अस्थि अवशेष थाईलैंड यात्रा पर गए थे, तब लगभग 55 लाख श्रद्धालुओं ने अत्यंत श्रद्धाभाव से इनके दर्शन एवं पूजा-अर्चना की थी।

उन्होंने कहा कि बौद्ध परंपरा में इन पवित्र अवशेषों का स्थान सर्वोच्च है तथा सांची जैसी पावन धरा का संरक्षक बनना उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।

इस अवसर पर छोटे गुरु पूज्य बानगल विमल तिस्स थेरी, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन (IBC) के संचालक कर्नल श्री यश सक्सेना, संस्कृति विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार गुप्ता सहित अनेक प्रबुद्धजन एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। सभी गणमान्य नागरिकों ने श्रद्धा एवं सम्मान के साथ भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के पवित्र अस्थि अवशेषों को मंगोलिया यात्रा हेतु भावभीनी विदाई दी।

अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर कलेक्टर श्री वर्मा सख्त

समस्त ट्रैक्टर-डम्पर स्वामियों व चालकों को आवश्यक दस्तावेज रखने के निर्देश

शिवपुरी. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण के लिए संयुक्त टीम द्वारा सघन जांच अभियान संचालित किया जा रहा है।

जांच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ ट्रैक्टर एवं डम्पर बिना नंबर प्लेट, बिना वैध दस्तावेज एवं बिना अनुमति के रेत परिवहन कार्य में संलग्न होकर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आवश्यक दस्तावेज रखने के निर्देश परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।समस्त ट्रैक्टर-डम्पर स्वामियों व चालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने वाहनों पर अनिवार्य रूप से मानकों के अनुसार स्पष्ट एवं वैध नम्बर प्लेट लगाएं। साथ ही संचालन के दौरान वाहन के समस्त वैध दस्तावेज जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, फिटनेस, बीमा, परमिट, प्रदूषण प्रमाणपत्र एवं चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और रेत परिवहन में संलग्न वाहनों के पास वैध रॉयल्टी, परिवहन अनुमति दस्तावेज साथ रखें।

नियम विरुद्ध संचालन पर होगी कार्यवाही जिले के विभिन्न मार्गों, चैक पोस्टों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग , खनिज सहित जिला प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई निरंतर जारी है। जांच के दौरान समस्त वैध दस्तावेजों तथा बिना टैक्स, ओवर लोडिंग अथवा नियम विरुद्ध रेत उत्खनन एवं परिवहन करने वाले ट्रैक्टर एवं डम्पर वाहनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम और खनिज नियमों एवं अन्य प्रचलित प्रावधानों के तहत चालानी, जप्ती एवं दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने समस्त वाहन स्वामियों एवं चालकों से कहा है कि वे शासन के नियमों का पालन सुनिश्चित करें एवं अवैध रेत परिवहन जैसी गतिविधियों में संलिप्त न हों, ताकि चेकिंग के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

मुरैना पुलिस ने पेश की ईमानदारी और तत्परता की मिसाल

भोपाल. मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं विश्वास बनाए रखने हेतु लगातार संवेदनशील और प्रभावी कार्यवाहियां की जा रही हैं।

इसी क्रम में मुरैना के थाना अम्बाह पुलिस ने तत्परता, सक्रियता एवं तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए कोचिंग संचालक के बैग से रास्ते में गुम हुई 06 लाख रुपये की राशि को बरामद कर सुरक्षित रूप से फरियादी के सुपुर्द किया है। पुलिस की इस सराहनीय कार्यवाही से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

19 मई को फरियादी योगेंद्र सिंह तोमर निवासी चंबल कॉलोनी अम्बाह द्वारा थाना अम्बाह में उपस्थित होकर सूचना दी गई कि वह दोपहर लगभग 1:38 बजे अपने पुत्र के साथ बाइक से सेंट्रल बैंक में 06 लाख रुपये जमा करने जा रहे थे। बाइक पर उनका पुत्र रुपयों से भरा बैग टांगे बैठा था। पेट्रोल पंप के पास बैग की चेन खुल जाने से रुपयों का बंडल सड़क पर गिर गया, जिसे पीछे से आ रहे एक बाइक सवार युवक द्वारा उठाकर ले जाया गया।

सूचना प्राप्त होते ही पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री धर्मराज मीना के निर्देशन में थाना प्रभारी अम्बाह निरीक्षक श्री वीरेश सिंह कुशवाह के नेतृत्व में तत्काल पुलिस टीम गठित कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का बारीकी से परीक्षण किया तथा मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। पुलिस द्वारा लगातार की गई मेहनत, सूझबूझ एवं तकनीकी जांच के परिणामस्वरूप घटना के मात्र 07 दिवस के भीतर बाइक सवार युवक की पहचान कर उससे 06 लाख रुपये की संपूर्ण राशि बरामद कर ली गई।

बरामद राशि को सुरक्षित रूप से फरियादी योगेंद्र सिंह तोमर को सुपुर्द किया गया। अपनी गुम हुई राशि वापस मिलने पर फरियादी एवं उनके परिजनों द्वारा मुरैना पुलिस का आभार व्यक्त किया गया।

मध्यप्रदेश पुलिस आमजन की सुरक्षा, सहायता एवं विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील एवं प्रभावी पुलिसिंग के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

अवैध उत्खनन पर प्रशासन की कार्यवाही

रौनीजा घाट पर एलएनटी मशीन और ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

शिवपुरी. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन के विरुद्ध जिला प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में करैरा में रौनीजा घाट पर देर रात कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध उत्खनन करते एक एलएनटी पॉकलेन मशीन और ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से जब्त किया। प्रशासन और पुलिस की टीम द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यवाही की गई। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार ललित शर्मा एवं सुनारी चौकी प्रभारी चेतन शर्मा भी मौजूद रहे।

सड़क दुर्घटना में घायल दो बुजुर्ग व्यक्तियों को त्वरित सहायता से पहुँचाया अस्पताल

भोपाल. गुना जिले के थाना राघौगढ़ क्षेत्र में डायल-112 जवानों की तत्पर एवं संवेदनशील कार्रवाई से सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल दो बुजुर्ग व्यक्तियों को समय पर अस्पताल पहुँचाकर उपचार उपलब्ध कराया गया। इस त्वरित कार्रवाई से दोनों घायलों को शीघ्र चिकित्सकीय सहायता मिल सकी। 27 मई को राज्य स्तरीय पुलिस कंट्रोल रूम डायल-112, भोपाल को सूचना प्राप्त हुई कि थाना राघौगढ़ क्षेत्र अंतर्गत वृंदावन होटल के सामने ए.बी. रोड पर एक मोटर साइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें 02 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तत्काल पुलिस सहायता की आवश्यकता है। सूचना प्राप्त होते ही थाना राघौगढ़ क्षेत्र में तैनात डायल-112 वाहन को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया।

जीआरपी भोपाल ने रेलवे स्टेशन से 02 वर्षीय बालक का अपहरण करने वाले आरोपी को 08 घंटे में किया गिरफ्तार

बालक को सकुशल परिजनों से मिलाया

सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर जीआरपी ने दिखाई तत्परता

भोपाल. मध्यप्रदेश पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता एवं पेशेवर जांच का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जीआरपी भोपाल ने रेलवे स्टेशन से अपहृत 02 वर्षीय बालक को मात्र 08 घंटे के भीतर सकुशल दस्तयाब कर उसके परिजनों को सौंप दिया।

पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

रेल पुलिस अधीक्षक भोपाल श्री अंकित जायसवाल के निर्देशन में इस गंभीर मामले को प्राथमिकता देते हुए तत्काल विशेष टीमों का गठन किया गया। थाना प्रभारी जीआरपी भोपाल निरीक्षक जहीर खान के नेतृत्व में गठित टीमों ने तकनीकी एवं मैदानी जांच के माध्यम से बालक को सुरक्षित बरामद करने में सफलता प्राप्त की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 26 मई को सीतू यादव निवासी जिला कटनी अपने पति के साथ मजदूरी की तलाश में भोपाल आई थीं। उनका पति मजदूरी के लिए चला गया, जबकि वे अपने 02 वर्षीय पुत्र के साथ भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 स्थित नई भवन के मुसाफिरखाने के सामने बैठी थीं। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति बच्चे को गोद में खिलाने के बहाने अपने साथ लेकर चला गया।

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी भोपाल ने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध कर रेलवे स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज का सूक्ष्म परीक्षण किया। जांच के दौरान फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति बालक को गोद में लेकर रेलवे स्टेशन परिसर से बाहर जाते हुए तथा इटारसी दिशा की ओर जाने वाली ट्रेन में सवार होता दिखाई दिया। पुलिस टीमों ने तकनीकी विश्लेषण एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसका पीछा किया। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप आरोपी को ट्रेन क्रमांक 12621 तमिलनाडु एक्सप्रेस के जनरल कोच से उतरते समय घेराबंदी कर पकड़ लिया गया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अपहृत बालक को सकुशल दस्तयाब कर उसे उसके परिजनों के सुपुर्द किया। बालक के सुरक्षित मिलने पर परिजनों ने जीआरपी भोपाल का आभार व्यक्त किया।

इस कार्रवाई ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि मध्यप्रदेश पुलिस नागरिकों की सुरक्षा एवं विशेषकर बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने नगर निगम आयुक्त श्री सिंघल के साथ जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण कार्यों का किया निरीक्षण

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में संचालित जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जिले में तालाबों के गहरीकरण तथा पर्याप्त जल पहुंच सुनिश्चित करने हेतु चैनल सफाई एवं जल संरक्षण के कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में कलेक्टर श्री शिवम वर्मा एवं आयुक्त नगर निगम श्री क्षितिज सिंघल द्वारा विभिन्न स्थलों पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री वर्मा द्वारा बिलावली तालाब में गहरीकरण कार्य, मोरोद-माचला चैनल सफाई कार्य, राऊ-बिलावली चैनल सफाई एवं पिचिंग कार्य तथा रालामंडल-बिलावली चैनल सफाई कार्य का जायजा लिया गया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि चैनलों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो तथा जहां अतिक्रमण पाया जाए वहां त्वरित रिमूवल की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही तालाबों के गहरीकरण एवं जल संरक्षण से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि जल संरक्षण एवं संवर्धन के ये कार्य भविष्य की जल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अभियान के माध्यम से जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर आमजन को दीर्घकालिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बिलावली तालाब के गहरीकरण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। बताया गया कि अब तक लगभग 32 हजार घनमीटर डिसिल्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा कार्य निरंतर जारी है।

कलेक्टर एवं निगमायुक्त ने राउ-बिलावली चैनल पर कॉलोनाइजरों द्वारा किए गए अतिक्रमण का भी निरीक्षण किया। इस दौरान भवन अधिकारी, जोन क्रमांक-13 को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। अपर आयुक्त श्री आशीष पाठक ने जानकारी दी कि निगम द्वारा पूर्व में पाइप डालकर किए गए अतिक्रमणों को भी जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हटाया गया है।

कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया कि राउ-बिलावली चैनल पर मौजूद सभी स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित कर निगम प्रशासन के समन्वय से शीघ्र हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इस दौरान रालामंडल-लिंबोदी चैनल चौड़ीकरण कार्य का निरीक्षण भी किया गया। यह कार्य पहली बार जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत प्रारंभ किया गया है। अधिकारियों ने संबंधित तहसीलदार श्री परमार को चिन्हित अस्थायी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए।

अधिकारियों ने बताया कि लिंबोदी-रालामंडल चैनल, लिंबोदी तालाब को भरने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रालामंडल पहाड़ी क्षेत्र का पूरा वर्षाजल इसी चैनल से होकर आता है। चैनल पर अतिक्रमण होने के कारण लिंबोदी तालाब पर्याप्त रूप से नहीं भर पा रहा है। इस पर कलेक्टर एवं निगमायुक्त ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त बायपास क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेन की सफाई नहीं होने से हर वर्ष बनने वाली जलभराव की स्थिति को रोकने के लिए निगमायुक्त श्री क्षितिज सिंघल ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों को तत्काल स्टॉर्म वाटर लाइन की सफाई कराने के निर्देश दिए।

व्यसन से बचो, सृजन में लगाओ-31 मई को बड़वानी में निकलेगी जिला स्तरीय जनजागरण यात्रा

इन्दौर बड़वानी जिले में व्यसन से बचो, सृजन में लगाओ अभियान के तहत 24 मई 2026 से व्यसन मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।

यह अभियान बड़वानी कलेक्टर जयंती सिंह के निर्देशन में अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग बड़वानी के संयुक्त तत्वावधान में संचालित हो रहा है।

युवा प्रकोष्ठ जिला समन्वयक श्री लखन विश्वकर्मा एवं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के उपसंचालक श्री रौनक सोलंकी ने बताया कि सप्ताहभर जिले की विभिन्न तहसीलों में जनजागरण, संपर्क अभियान, संकल्प सभाएँ, मानव श्रृंखला, चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक तथा व्यसन मुक्ति से जुड़े रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज को नशामुक्त, स्वस्थ एवं संस्कारवान बनाना है। इसके अंतर्गत गायत्री परिवार के कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र-छात्राएं घर-घर संपर्क कर लोगों को तंबाकू, शराब एवं अन्य नशों के दुष्परिणामों से अवगत करा रहे हैं तथा व्यसन त्यागने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अभियान का समापन 31 मई "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" के अवसर पर जिला स्तरीय जन जागरण यात्रा के रूप में होगा। स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ बड़वानी से भव्य रैली एवं व्यसन मुक्ति मानव श्रृंखला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में परिजन, युवा, मातृशक्ति एवं नागरिकजन सहभागिता कर नशामुक्त समाज निर्माण का सामूहिक संकल्प लेंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक गोपाल गावंडे द्वारा पंकज प्रिंटर्स एण्ड पैकेजिंग एलयूएन-22 सेक्टर एफ, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं जी-1, कॉस्मिक रिजेन्सी 117 गोकुल नगर कनाड़िया इंदौर म.प्र. से प्रकाशित।
प्रधान संपादक-गोपाल गावंडे (पी.आर.बी.) एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार (समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)।